

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2022—आश्विन 8, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 अगस्त 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री गोविन्दराम चुरेन्द्र, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, सरगुजा संभाग अंबिकापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त, सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री संजय कुमार अलंग, भा.प्र.से. (2004), आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 अगस्त 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री आनंद कुमार मसीह, भा.प्र.से. (2013), उपायुक्त (राजस्व), संभागायुक्त कार्यालय, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के पद पर पदस्थ करता है।

श्री आनंद कुमार मसीह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 अगस्त 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा सुश्री रीता शांडिल्य, भा.प्र.से. (2002), सदस्य, राजस्व मंडल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, राजस्व मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 अगस्त 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री सारांश मित्र, भा.प्र.से. (2010), प्रबंध संचालक, छ.ग. रोड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. औद्योगिक विकास निगम को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री सारांश मित्र, भा.प्र.से. द्वारा नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005), सचिव, वन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक ई 1-13/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारत सरकार, केबिनेट नियुक्ति समिति, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 36/02/2022-EO(SM-I), दिनांक 10-08-2022 के तारतम्य में डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995), प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को प्रबंध संचालक, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से सौंपते हुए कार्यमुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 अगस्त 2022

क्रमांक 2306/एफ 1-8/2019/13/1.—राज्य शासन के निम्नलिखित आदेशों से श्री हर्ष गौतम, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को जनरेशन/ट्रेडिंग/होलिडिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन डायरेक्टर नामित किया गया है :—

| आदेश क्रमांक | कंपनी का नाम |
|---|-----------------------------------|
| 47/एफ 1-1/2019/13/1 दिनांक 08-01-2021 | जनरेशन कंपनी में पदेन डायरेक्टर |
| 49/एफ 1-1/2019/13/1 दिनांक 08-01-2021 | ट्रेडिंग कंपनी में पदेन डायरेक्टर |
| 1489/एफ 1-1/2019/13/1 दिनांक 18-08-2020 | होलिडिंग कंपनी में पदेन डायरेक्टर |

2. विभाग के आदेश 420/एफ 1-8/2019/13/1 दिनांक 13-05-2022 से श्री हर्ष गौतम, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के स्थान पर श्री मनोज खरे, आत्मज स्व. श्री प्रमोद कुमार खरे को प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड नियुक्त किया गया है. अतः उक्त कंपनियों के अंतर्नियम की कंडिका-77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री हर्ष गौतम को उक्त जनरेशन/ट्रेडिंग/होलिडिंग कंपनी लिमिटेड के संचालक के पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

3. यह आदेश भूतकालीन दिनांक 13-05-2022 से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 अगस्त 2022

क्रमांक 2308/एफ 1-8/2019/13/1.—राज्य शासन के निम्नलिखित आदेशों से अधिकारियों को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होलिडिंग/ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में संचालक, अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है :—

| क्र. (1) | अधिकारी का नाम (2) | कंपनी का नाम (3) | पद (4) | नियुक्ति आदेश (5) |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|
| 1. | श्री अंकित आनंद, आईएएस | छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होलिडिंग कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड | अध्यक्ष एवं संचालक अध्यक्ष एवं संचालक | क्रमांक 83/एफ 1-5/2018/13/1 दिनांक 19-01-2019. क्रमांक 85/एफ 1-5/2018/13/1 दिनांक 19-01-2019. |
| 2. | श्रीमती अलरमेल मंगई डी, आईएएस | छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होलिडिंग कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड | संचालक संचालक | क्रमांक 38/एफ 1-9/2008/13/1 दिनांक 07-01-2021. क्रमांक 40/एफ 1-9/2008/13/1 दिनांक 07-01-2021. |
| 3. | श्रीमती उज्ज्वला बघेल | छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होलिडिंग कंपनी लिमिटेड. | प्रबंध संचालक एवं संचालक | क्रमांक 1684/एफ 1-8/2019/13/1 दिनांक 21-09-2020. |
| 4. | श्री राजेश वर्मा | छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड. | प्रबंध संचालक एवं संचालक | क्रमांक 850/एफ 1-8/2019/13/1 दिनांक 27-04-2020. |
| 5. | श्री एन. के. बिजौरा | छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होलिडिंग कंपनी लिमिटेड. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड. | संचालक संचालक | क्रमांक 858/एफ 1-9/2008/13/1 दिनांक 04-05-2020. क्रमांक 862/एफ 1-9/2008/13/1 दिनांक 04-05-2020. |

2. छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के अधिसूचना क्र. 1686/एफ-21/13/09/13/2 दिनांक 08-06-2022 से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का क्रमशः छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में विलय किया गया है। तत्संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के परिपत्र क्र. 01-01/08 दिनांक 07-07-2022 से होल्डिंग कंपनी का ट्रांसमिशन कंपनी में एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के परिपत्र क्र. 02-11/मर्जर/2407 दिनांक 07-07-2022 से ट्रेडिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में विलय किया गया है।
3. अतः उक्त विलय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा ऊपर पैरा-1 की तालिका में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त कंपनी के संचालक, अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के पद से कार्यमुक्त करता है।
4. यह आदेश दिनांक 08-07-2022 से प्रभावशील होगा।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 अगस्त 2022

क्रमांक 2310/एफ 1-8/2019/13/1.—छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के अधिसूचना क्र. 1686/एफ-21/13/09/13/2 दिनांक 08-06-2022 से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का क्रमशः छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में विलय किया गया है।

2. उक्त विलय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय आदेश क्रमांक 1962/एफ-21/13/2009/13/2 दिनांक 07 जुलाई, 2022 से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन/ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संचालक मण्डल की संशोधित सेटअप जारी की गई है, जिसके अनुसार भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा एवं वित्त विभाग तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन/ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में पदस्थ प्रबंध निदेशक को अन्य कंपनियों में पदेन निदेशक नियुक्त किये जाने का प्रावधान है, जो कि निम्नानुसार है :—

| राज्य शासन एवं कंपनी के पदस्थ अधिकारी (1) | कंपनी जिसमें पदेन निदेशक होंगे (2) |
|--|---|
| भारसाधक सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग | निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन/ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड |
| भारसाधक सचिव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग | निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन/ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड |
| प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड | निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड |
| प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड | निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड |

3. राज्य शासन एतद्वारा उक्त तालिका अनुसार भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा संबंधित विभाग/कंपनियों में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से उक्त तालिका के कालम-2 में दर्शित कंपनियों में पदेन निदेशक नियुक्त माने जावेंगे तथा संबंधित विभागों में भारसाधक सचिव अथवा प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त होने के दिनांक से कंपनियों के निदेशक के पद से भी पदमुक्त माने जावेंगे।

4. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार हिंगवे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 सितम्बर 2022

क्रमांक एफ 07-27/2019/32.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 11-10-2021 द्वारा अंबिकापुर विकास योजना, 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

अंबिकापुर विकास योजना 2021 में उपांतरण

| क्र. (1) | ग्राम का नाम (2) | खसरा क्र. (3) | रकबा (हेक्टेयर में) (4) | अंबिकापुर विकास योजना 2021 में दर्शित भू उपयोग (5) | अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण (6) |
|-------------|---------------------|------------------|-------------------------------|--|---|
| 1. | संजयनगर पहल. 51 | 382 | 0.97 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 2. | | 383 | 1.40 हे. में से 1.329 हे. | कृषि भूमि एवं मार्ग | आवासीय (मार्ग को छोड़कर) |
| 3. | | 384 | 0.20 हे. में से 0.01 हे. | कृषि भूमि एवं मार्ग | आवासीय (मार्ग को छोड़कर) |
| 4. | | 386 | 0.11 हे. में से 0.1042 हे. | कृषि भूमि एवं मार्ग | आवासीय (मार्ग को छोड़कर) |
| 5. | | 398 | 0.58 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 6. | | 399 | 0.22 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 7. | | 400 | 0.76 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 8. | | 402 | 0.41 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 9. | | 403 | 0.34 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 10. | | 404 | 0.12 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 11. | | 405 | 0.25 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 12. | | 408 | 0.15 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 13. | | 410 | 0.89 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 14. | | 411 | 0.56 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 15. | | 412 | 0.55 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 16. | | 413 | 0.28 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 17. | | 414 | 0.32 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 18. | | 415 | 0.22 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 19. | | 416 | 0.12 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 20. | | 417 | 1.74 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------------|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 21. | | 418 | 0.38 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 22. | | 424 | 0.59 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 23. | | 425 | 1.26 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 24. | | 426 | 0.26 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 25. | | 427 | 0.89 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 26. | | 429 | 0.43 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 27. | | 430/1 | 0.52 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 28. | | 431/1 | 0.66 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 29. | | 432 | 1.49 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 30. | | 433 | 0.12 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 31. | | 434 | 0.01 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 32. | | 435 | 0.01 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 33. | | 436 | 0.02 हे. | कृषि भूमि एवं वाणिज्यिक | आवासीय |
| 34. | | 439 | 0.33 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 35. | | 440 | 0.01 हे. में से 0.0048 हे. | वाणिज्यिक एवं मार्ग | आवासीय (मार्ग को छोड़कर) |
| 36. | | 450 | 0.34 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 37. | | 451 | 0.95 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| 38. | | 452 | 0.48 हे. | कृषि भूमि | आवासीय |
| योग | | 38 | 18.668 हे. | | |

2. उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की अटल विहार योजना के प्रयोजन हेतु है।

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

4. अतः राज्य शासन एतद्वारा अंबिकापुर विकास योजना, 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण अंबिकापुर विकास योजना, 2021 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप-सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 अगस्त 2022

क्रमांक/5286/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र./5923/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए, मण्डी क्षेत्र में प्रदेश के बाहर से लाई गई (आयातित) दलहन, तिलहन, गेहूं पर, प्रति 100 रुपये के मूल्य पर, रु. 0.50 (पचास पैसे) की दर से मण्डी शुल्क तथा रु. 0.25 (पच्चीस पैसे) की दर से कृषक कल्याण शुल्क निर्धारित करती है।

ये दरें, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष तक के लिये प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 अगस्त 2022

क्रमांक/5286/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5286/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 रायपुर दिनांक 29-08-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव।

Nava Raipur, Atal Nagar 29th August 2022

No./5286/D-15/116/Part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, fixes the Market Fees at the rate of Rs. 0.50 (fifty paise) and Farmer Welfare Fees at the rate of Rs. 0.25 (twenty five paise) on the value of per 100 rupees on pulses, oil seeds, wheat (imported) brought from outside the State into the market area, by making partial amendment in this department's Notification No. 5923/D-15/116/Part-2/2004/14-2, dated 30th November, 2021.

These rates, shall be effective for 01 year from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 अगस्त 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2021-22.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम/नगर (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|--|
| बिलासपुर | रतनपुर | जोगीपुर | 0.675 | मंगला-भैंसाझार मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-9-2022 को (समय) 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम जोगीपुर पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|--------|--|---|--|
| (एक) | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | मंगला-भैंसाझार मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु. |
| (दो) | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 1 |
| (तीन) | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | — |
| (चार) | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| (पांच) | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| (छः) | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| (सात) | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. | — | हां-उल्लेखित भूमि पर मंगला-भैंसाझार मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है. |
| (आठ) | परियोजना की कुल लागत | — | 111.96 करोड़ (एक सौ ग्यारह करोड़ छियानबे लाख) |
| (नौ) | परियोजना से होने वाले लाभ | — | — |
| (दस) | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/9982/क/भू-अर्जन/04 अ 82/2019-20.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम/नगर (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|-------------|--------------|------------------|-------------------|---|
| कोरबा | करतला | चोरभट्टी | 0.777 हे./1.92 ए. | मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण. |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 12-10-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम चोरभट्टी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण. |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 11 |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | निरंक |
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 5. | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. | — | हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — | 1713.18 लाख |
| 9. | परियोजना से होने वाले लाभ | — | आवागमन की सुविधा |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/9984/क/भू-अर्जन/05 अ 82/2019-20.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम/नगर (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|-------------|--------------|------------------|-------------------|---|
| कोरबा | करतला | कछार | 0.065 हे./0.16 ए. | मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण. |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 14-10-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम कछार नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण. |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 01 |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | निरंक |
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 5. | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. | — | हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — | 1713.18 लाख |
| 9. | परियोजना से होने वाले लाभ | — | आवागमन की सुविधा |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/9988/क/भू-अर्जन/03 अ 82/2019-20.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम/नगर (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|-------------|--------------|------------------|-------------------|---|
| कोरबा | करतला | मदवानी | 0.243 हे./0.60 ए. | मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण. |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 19-10-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम मदवानी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण. |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 02 |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | निरंक |
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 5. | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. | — | हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — | 1713.18 लाख |
| 9. | परियोजना से होने वाले लाभ | — | आवागमन की सुविधा |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

रा.प्र.क्र. 18/10613/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम/नगर (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|---|
| कोरबा | पाली | परसदा | 0.076 हे. | ए.डी.बी. परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली-सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन. |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 04-11-2022 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | ए.डी.बी. परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली-सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन. |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 01 परिवार |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 01 परिवार |
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 5. | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. | — | हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — | रुपये 55.96 करोड़ |
| 9. | परियोजना से होने वाले लाभ | — | परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के समस्त ग्रामवासी लाभान्वित होंगे. |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

रा.प्र.क्र. 19/10657/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम/नगर (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|---|
| कोरबा | पाली | पोलमी | 0.3789 हे. | ए.डी.बी. परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली-सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन. |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-11-2022 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | ए.डी.बी. परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली-सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन. |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 15 परिवार |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 15 परिवार |
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 5. | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. | — | हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — | रुपये 55.96 करोड़ |
| 9. | परियोजना से होने वाले लाभ | — | परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के समस्त ग्रामवासी लाभान्वित होंगे. |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10659/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम/नगर (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| कोरबा | कटघोरा | कनबेरी | 4.18 एकड़ | कुदुरमाल एनीकट योजना की निर्माण हेतु |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10-10-2022 को समय 12.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन कनबेरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | कुदुरमाल एनीकट योजना की निर्माण हेतु |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 20 परिवार |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 20 परिवार |
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 5. | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. | — | हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — | रु. 3179.12 लाख |
| 9. | परियोजना से होने वाले लाभ | — | परियोजना से औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय निस्तार एवं भू-जल संवर्धन इत्यादि होगा. परियोजना से कुल 03 ग्राम लाभान्वित होंगे. |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | परियोजना से कुल 03 ग्राम में जल संवर्धन होगा तथा निस्तार एवं पेयजल की समस्या हल होगी. |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

रा.प्र.क्र. 24/10664/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम/नगर (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|---|
| कोरबा | पाली | पोंड़ी | 0.6113 हे. | ए.डी.बी. परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली-सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन. |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31-10-2022 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | ए.डी.बी. परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली-सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन. |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 15 परिवार |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 15 परिवार |
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 5. | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. | — | हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — | रुपये 55.96 करोड़ |
| 9. | परियोजना से होने वाले लाभ | — | परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के समस्त ग्रामवासी लाभान्वित होंगे. |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

रा.प्र.क्र. 26/10668/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम/नगर (3) | क्षेत्रफल (4) | लोक प्रयोजन का विवरण (5) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|---|
| कोरबा | पाली | नानपुलाली | 0.1958 हे. | ए.डी.बी. परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली-सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन. |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-10-2022 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | ए.डी.बी. परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली-सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन. |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 09 परिवार |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 09 परिवार |
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 5. | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. | — | हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — | रुपये 55.96 करोड़ |
| 9. | परियोजना से होने वाले लाभ | — | परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के समस्त ग्रामवासी लाभान्वित होंगे. |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

कोण्डागांव, दिनांक 4 अगस्त 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11)

क्रमांक/2421/अ-82/भू-अर्जन/2021-22/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम 11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला | तहसील | ग्राम/नगर | क्षेत्रफल कुल खसरा कुल रकबा | लोक प्रयोजन का विवरण |
|------------|--------|-----------|-----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| कोण्डागांव | केशकाल | तोसकापाल | 07 0.476 हे. | तोसकापाल-तरईबेड़ा-बड़ेराजपुर मार्ग के कि.मी. 1/8 गौरबहार नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आने वाले ग्राम तोसकापाल की निजी भूमि. |

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन तोसकापाल पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

| | | | |
|------|---|---|--|
| एक | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | तोसकापाल-तरईबेड़ा-बड़ेराजपुर मार्ग के कि.मी. 1/8 गौरबहार नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. |
| दो | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 07 |
| तीन | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 0 |
| चार | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| पांच | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| छः | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हाँ 0.476 हेक्टेयर |
| सात | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. | — | हां |
| आठ | परियोजना की कुल लागत | — | 945.01 लाख |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| नौ | परियोजना से होने वाले लाभ | — | प्रस्तावित सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय आने जाने हेतु वर्ष पर्यन्त आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी. |
| दस | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | 5.00 लाख |
| ग्यारह | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

| कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | (1) | (2) |
|---|--------------|-------|
| | 1/21 | 0.008 |
| | 3/3 | 0.020 |
| | 5/3 | 0.052 |
| कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2022 | 5/2 | 0.065 |
| | 18/2 | 0.057 |
| क्रमांक/10000/भू-अर्जन/अ-82/2022. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— | 67 | 0.061 |
| | 86 | 0.125 |
| | 73/2, 74/2 | 0.093 |
| | 12/1 | 0.097 |
| | 13/1 | 0.113 |
| | 64/1 | 0.101 |
| | 66 | 0.020 |
| | 12/2 | 0.004 |
| | 16/1 | 0.077 |
| अनुसूची | 78/1 | 0.069 |
| | 85/5 | 0.012 |
| (1) भूमि का वर्णन— | 78/2 | 0.053 |
| (क) जिला-कोरबा | 61/2 | 0.057 |
| (ख) तहसील-कटघोरा | 85/1 | 0.153 |
| (ग) नगर/ग्राम-अभयपुर | 95/1 में से | 0.053 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.636 हेक्टेयर | 34/1 में से | 0.053 |
| | 34/1 में से | 0.053 |
| खसरा नम्बर | 34/1 में से | 0.053 |
| | 34/1 में से | 0.053 |
| (1) | 95/1 में से | 0.053 |
| | 95/1 में से | 0.020 |
| 8/2 | 223/1 में से | 0.024 |
| 16/2 | 223/1 में से | 0.008 |
| | 223/1 में से | 0.016 |

| (1) | (2) |
|--------------|-------|
| 223/1 में से | 0.020 |
| 223/1 में से | 0.028 |
| 3/1 | 0.041 |
| 3/2 | 0.041 |
| 96/2 | 0.109 |
| 96/5 | 0.053 |
| 96/1 | 0.254 |
| 223/5, 224/2 | 0.069 |
| 73/1, 74/1 | 0.093 |
| 4 | 0.004 |
| 2/3 | 0.065 |
| 95/1 में से | 0.053 |
| 34/1 में से | 0.077 |
| योग | 2.636 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -कटघोरा
व्यपवर्तन योजनान्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक 04/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-रतनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मझवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.578 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 1/1/6 | 0.202 |
| 371/4 | 0.012 |
| 1/1/14 | 0.202 |
| 1/1/12 | 0.162 |
| योग | 0.578 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुडा
व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक 11/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-रतनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.966 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 1858 | 0.049 |
| 1859 | 0.049 |
| 1868 | 0.194 |
| 1963/1, 1964/1 | 0.137 |
| 1963/2, 1964/2 | 0.137 |
| 1970 | 0.360 |

| (1) | (2) |
|------|-------|
| 1855 | 0.040 |
| योग | 9 |
| | 0.966 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—लारीपारा व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक 12/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-रतनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उमरमरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.213 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 9 | 0.093 |
| 19 | 0.716 |
| 612/1 | 0.202 |
| 612/2 | 0.202 |
| योग | 4 |
| | 1.213 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—लारीपारा व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक 13/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-रतनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खरगहनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 729 | 0.113 |
| 726/3घ | 0.081 |
| योग | 2 |
| | 0.194 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—लारीपारा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक 16/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

| अनुसूची | | (1) | (2) |
|--|----------------|----------|-------|
| (1) भूमि का वर्णन- | | 46/3 | 0.405 |
| (क) जिला-बिलासपुर | | 114/2 | 0.526 |
| (ख) तहसील-कोटा | | 112 | 0.482 |
| (ग) नगर/ग्राम-धूमा | | 106, 107 | 0.717 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.327 हेक्टेयर | | 108 | 0.749 |
| | | 100 | 0.024 |
| | | 103 | 0.356 |
| खसरा नम्बर | रकबा | 109 | 0.615 |
| | (हेक्टेयर में) | 99/1 | 0.117 |
| (1) | (2) | 101 | 0.320 |
| | | 104 | 0.251 |
| 243/5 | 0.077 | 57 | 0.393 |
| 442/3 | 0.101 | 99/2 | 0.121 |
| 243/2 | 0.028 | 82 | 0.559 |
| 444/2 | 0.121 | 81/2 | 0.219 |
| योग | 4 | 63, 81/1 | 0.259 |
| | | 110/2 | 0.012 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांसाझाल-तेन्दुवा योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर निर्माण हेतु. | | 64 | 0.085 |
| | | 62 | 0.304 |
| | | 61 | 0.700 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है. | | 67/8 | 0.328 |
| | | 67/7 | 0.809 |
| | | 67/4 | 0.223 |
| बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2022 | | 67/5 | 0.692 |
| | | 67/2 | 0.049 |
| क्रमांक 17/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- | | 47/3 | 0.482 |
| | | 114/1 | 0.644 |
| | | 113/1 | 0.215 |
| | | 113/2 | 0.215 |
| | | 111/2 | 0.810 |
| | | 53 | 0.741 |
| | | 111/1 | 0.543 |
| | | 54 | 0.656 |
| | | 58 | 0.700 |
| अनुसूची | | 47/4 | 0.809 |
| | | 46/2 | 0.405 |
| (1) भूमि का वर्णन- | | 108 | 0.012 |
| (क) जिला-बिलासपुर | | 104 | 0.036 |
| (ख) तहसील-कोटा | | 98/4 | 0.109 |
| (ग) नगर/ग्राम-बांसाझाल | | 98/3 | 0.113 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.443 हेक्टेयर | | 135 | 0.089 |
| | | 136/1 | 0.036 |
| | | 137, 138 | 0.053 |
| खसरा नम्बर | रकबा | 309/2 | 0.061 |
| | (हेक्टेयर में) | 309/3 | 0.028 |
| (1) | (2) | 311, 312 | 0.182 |
| | | 313/1 | 0.146 |
| 115 | 0.085 | | |

| (1) | (2) | अनुसूची | |
|--|--------|---|------------------------|
| 322/1, 322/2 | 0.089 | (1) भूमि का वर्णन- | |
| 67/4 | 0.121 | (क) जिला-बिलासपुर | |
| 67/3 | 0.093 | (ख) तहसील-बेलगहना | |
| 67/6 | 0.089 | (ग) नगर/ग्राम-पण्डरापथरा | |
| 39/2 | 0.077 | (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.947 हेक्टेयर | |
| 17 | 0.117 | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| 19/1 | 0.126 | | |
| 22/2 | 0.081 | (1) | (2) |
| 23 | 0.121 | | |
| 20 | 0.049 | | |
| योग | 17.443 | 94/4 | 0.162 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांसाझाल-तेन्दुवा जलाशय योजना के बण्ड एवं डूब क्षेत्र बांयी/दायी तट नहर निर्माण कार्य हेतु. | | 264/7 | 0.405 |
| | | 267/3 | 0.121 |
| | | 264/6 | 0.162 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है. | | 104/6 | 0.097 |
| | | योग | 0.947 |
| बिलासपुर, दिनांक 26 अगस्त 2022 | | | |
| क्रमांक 46/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— | | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुडा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण (पूरक) कार्य हेतु. | |
| | | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है. | |
| | | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. | |

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 9 जून 2022

क्रमांक/65/04/योजना/बीओसी/2022/121.—“भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित “निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना” में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 53 दिनांक 23-05-2017 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :—

(क) योजना का प्रावधान :—

1. योजना का नाम “निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना” होगा.

2. योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लागू योजना खेलों इण्डिया योजना के अंतर्गत चिन्हित खेल जैसे-ऐथलेटिक, कबड्डी, खोखो, फुटबाल, बॉलीबॉल, हेण्डबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, अंतर्गत स्वीकृत/मान्यता प्राप्त समस्त खेलों में जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार प्रदाय किया जावेगा —
 - (i) जिला स्तर पर राशि रुपये – 1,000/-
 - (ii) संभाग स्तर पर राशि रुपये – 2,000/-
 - (iii) राज्य स्तर पर राशि रुपये – 5,000/-
 - (iv) राष्ट्रीय स्तर पर राशि रुपये-50,000/-

3. योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ख) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. योजना के तहत प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे को लाभ की पात्रता होगी.
2. योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को देय होगा, जिनकी उत्कृष्टता खेल विभाग द्वारा प्रमाणित हो.

(ग) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन आवेदक स्वयं/च्चाईस सेंटर/संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है.
2. योजनांतर्गत उत्कृष्टता प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
3. योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज—
 - 3.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की प्रति.
 - 3.2 हितग्राही के पुत्र/पुत्री के आधार कार्ड की प्रति.
 - 3.3 खेल विभाग द्वारा जारी उत्कृष्टता प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति.
 - 3.4 बैंक पास बुक की प्रति.

टीप :— ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.

- (घ) **स्वीकृति का अधिकार :—** पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी.
- (ङ) **भुगतान की प्रक्रिया :—** योजनांतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजनांतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदक/आवेदिका के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित किया जावेगा.
- (च) **विसंगति का निराकरण :—** योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा.

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.

राजेश कुमार पात्रे,
सचिव.

राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 10 अगस्त 2022

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

CGFC39
(See Rule 80)

पृ. क्रमांक 282/छ.ग.रा.मं./बिलासपुर/2022.—Certified that we have in the AN/FN of this day on 10-08-2022 respectively received charge of the Office of the Incharge President, Board of Revenue, C.G., Bilaspur vide GAD's order No. E-1-03/2022/एक-2, Nawa Raipur, dated 08-08-2022 and that the officer receiving charge travelled during joining time on +P.M. (mention dates).

Relieving Officer : Reeta Shandilya

हस्ता./-
अवर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd August 2022

No. 1056/Confdl./2022/II-2-1/2022.— The following Members of Higher Judicial Service as Specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

| S. No. (1) | Name & presently posted as (2) | From (3) | To (4) | Sessions Division (5) | Posted as (6) |
|---------------|---|-------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | Shri Ashok Kumar Sahu, District and Sessions Judge. | Surajpur | Bilaspur | Bilaspur | District and Sessions Judge. |
| 2. | Shri Govind Narayan Jangde, Judge Family Court. | Dhamtari | Surajpur | Surajpur | District and Sessions Judge. |

By order of the High Court,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.